मोदी राज में बैंक अधिकारी बढ़ते एनपीए से ही नहीं अपनी घटती साख से भी जूझ रहे

ग्राउंड जीरो से विवेक की रिपोर्ट

कहने को आल इंडिया बैंक ऑफिसर कनफेडरेशन ने हमेशा अपने कर्मचारियों के हित के लिए स्टैंड लिया है। और यह भी कि जिसमें कर्मचारियों का हित निहित है उसी में देश का भी हित है। मंच से आती एआइबीओसी के प्रतिनिधि हरमिंदर सिंह की आवाज में मुखरित होता उपरोक्त कथन असलियत के कितना करीब है इसकी पड़ताल मजदूर मोर्चा टीम ने की।

चार फरवरी को एआइबीओसी के देशव्यापी मार्च एवं विरोध प्रदर्शन का जुलूस दिल्ली में बाराखम्भा रोड से शुरू होकर जंतर मंतर तक गया। जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में देश के सभी 21 पीएसयू बैंकों के अधिकारियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करायी।

रांची से आये एआइबीओसी के सेक्रटरी एवं बैंक आफ इंडिया के सुनील लाकरा का मानना है कि तीस हजार बैंक अधिकारियों की उपस्थिति के साथ उनका यह धरना प्रदर्शन अत्यंत सफल रहा। लाकरा के अनुसार, एआइबीओसी सरकार से विशफुल डीफाल्टरों के नाम उजागर करने की मांग के साथङ्क साथ बैंक आफ बड़ोदा, देना बैंक और विजय बैंक के विलय को निरस्त करने का विरोध करती है। साथ ही बैंकों में खाली पड़े स्थानों पर नयी भर्तियाँ करने एवं पांच दिवसीय कार्यप्रणाली लागू करने का भी आह्वान किया गया है।

लाकरा ने माना कि इन सभी मुद्दों में बैंक आफ इंडिया का मुख्य मुद्दा है, बैंकों का आपस में विलय। विलय से क्या बैंक आपस में मजबूत नहीं होंगे, जैसा कि वित्त मंत्री जेटली का दावा है, इसपर लाकरा ने कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, उल्टा ये सरकार की साजिश है जिससे कि बैंक सेक्टर का निजीकरण किया जा सके। सरकार पहले तीन अलग-अलग कार्यसंस्कृति के संस्थानों को आपस में मिलाएगी फिर जब तीनो का सामंजस्य नहीं होने की सूरत में बैंक की परफॉरमेंस खराब होगी तो यही सरकार इसे ही बैंक की कमियाँ बताते हुए निजी हाथों में दे देगी। दरअसल ये सब बैंकों को सिर्फ निजी हाथों में देने की तैयारी ही है।

बैंक आफ बड़ोदा की वरिष्ठ अधिकारी अमिता आर्य ने बताया कि इससे पहले वर्ष 201। में एसबीआई में 6 इकाइयों के विलय के समय भी विरोध दर्ज कराया गया था पर इस सरकार के मुंह तो मानो जैसे खून लग गया है। आर्य ने बताया कि एसबीआई के उस मर्जर से जो छोटी इकाइयों के कर्मी थे उनका बहुत नुकसान हुआ है। जो अलाऊंस उन्हें पहले मिला करते थे वो विलय के बाद से लगभग नदारद ही हैं। यहाँ तक कि उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान भी जाता रहा है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे नदी सागर में मिल कर अपना अस्तित्व खो चुकी है। पर इंसान कोई नदी नहीं, हमारे अधिकारों में प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है।

धरने में शामिल पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों की मुख्य मांग थी कि बड़े विशफुल डिफाल्टरों के नाम उजागर किये जायें। बैंक अधिकारियों ने उग्र स्वर में कहा कि जब मोदी सत्ता में आने को छटपटा रहे थे तब हर मंच से घोषणा करते घूमते थे कि जब हम सत्ता में आयेंगे तो काले धन और बैंक का रुपया दबाये बैठे लोगों से सब पैसा वसूल करेंगे। पर हुआ क्या, उल्टा नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल भाई और ना जाने ऐसे कितने ही नाम हैं, जिनका जिक्र तक मुख्य मीडिया में नहीं आया और जो हजारों करोड़ ले कर जा चुके हैं। हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि जानबूझ कर लोन ना चुकाने वाले पूंजीपतियों के नाम उजागर किये जाएं।

पीएनबी के ही युवा अधिकारियों के एक झुण्ड से बातचीत करने पर उनका दर्द बैंक के मुख्य मुद्दों से अलग एक अन्य महत्वपूर्ण मसले पर छलकता दिखा। लतिका ने बताया कि वर्ष 2011 में उन्होंने एसबीआई में बतौर पीओ अपना पदभार संभाला था। तबसे लेकर नोटबंदी तक उन्हें हर रोज बैंक कर्मी होने पर फक्र हुआ करता था। अचानक एक काली रात को देश का प्रधानमंत्री नोटबंदी की घोषणा करता है और आरबीआई की इज्जत के साथ-साथ पूरे वित्तीय संस्थानों की साख लूट लेता है। लतिका ने बताया कि नोटबंदी जिस दिन हुई उसके बाद से लेकर जबतक सरकार का असल चेहरा सामने नहीं आया तब तक वो स्वंय अपने मित्रों, ग्राहकों सबको यकीन दिलाती रहीं कि कुछ बेहतर ही होगा, शांति बनाये रखें। पर जैसे जैसे दिन बीते सरकार एक के बाद एक पूंजीपतियों के पक्ष के फैसले लेती दिखी। जिन-जिन लोगों को लतिका सरकार के पक्ष में समझाया करती थीं वो आज उन्हें गालियाँ तक दे जाते हैं।

सेवाग्राम महाराष्ट्र से आये गणेश वाघमारे ने बताया कि नोटबंदी में सरकार ने कर्मियों को अतिरिक्त भुगतान की घोषणा भी की थी पर उसका कुछ अता-पता नहीं है आजतक। भुगतान न मिलने का कोई खास मलाल तो नहीं पर बतौर बैंकर जो इज्जत गंवाई उसका भुगतान शायद अब न हो सके। गणेश और उनकी साथी आरती ने सम्मिलित रूप से बताया कि नोटबंदी के दौरान उन्होंने अपने सभी ग्राहकों से शांति बनाये रखने की अपील की। क्योंकि सेवाग्राम एक छोटा सा शहर है इसलिए लगभग सभी लोग गणेश और आरती को बाइज्जत जानते थे। पर मोदी के एक फैसले से दुनिया बदल सी गई। अब वही लोग गणेश और आरती को एक चोर के रूप में देखते हैं। क्योंकि नोटबंदी की असफलता का सेहरा सरकार ने बिकाऊ मीडिया के माध्यम से बैंक कर्मचारियों के उपर डाल कर अपना पल्ला झाड़ लिया है।

भीलवाड़ा राजस्थान से आयी 27 वर्षीय मनीषा ने बताया कि नोटबंदी की भीड़ कोई मसला नहीं था। पर जब सरकार रोज झूठ बोलने लगी तो वही भीड़ जो रोज दुआ सलाम करती थी और अपनी बेटी की तरह व्यहवहार करती थी हमसे, मां-बहन की गालियां तक देने लगी। खून के आंसू रोये हैं हम तब। रूआंसी होती मनीषा और उनके अन्य सभी युवा साथियों की मांग है कि बैंक कर्मियों की इस बेइज्जती के लिए सरकार माफी मांगे और नोटबंदी के पाप की गठरी मोदी अपने सिर उठायें न कि उन पर लादें।

यूको बैंक दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी तरुण जोशी मोटरसाइकिल वाले झुंड की अगुवाई करते हुए बोले कि मोदी के परम भक्तों में यदि किसी का नाम लिखना होता तो वो सिर्फ खुद अपना नाम लिखते पर अब लगता है कि बड़ा धोखा हुआ। मोदी के भाषणों से जोशी को यकीन था कि सब तारे मोदी जी जमीन पर उतार लायेंगे पर ऐसा हुआ नहीं। जोशी ने बताया कि बैंकों में रिक्त पदों की संख्या बढती ही जा रही है, सरकार न तो नयी भर्तियाँ कर रही है न ही ऐसी कोई नीयत दिख रही है सरकार की। बड़ी संख्या में लोग सेवानिवृत हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बैंक को एक कर्मी से कई-कई काम लेने पड़ रहे हैं। ऊपर से एनपीए की समस्या बढ़ने से बैंक का सारा पैसा प्रोविजनिंग करने में जा रहा है तो बैंक लोन कहां से बांटे। अब तो बस हम रिटायर हो जाएं तो ये जान बचे वरना देखिये न इस बुढापे में मोटरसाइकिल पर धरना देना क्या कोई कम जोखिम की बात है?

एनपीए के मुद्दे पर हरमिंदर सिंह ने स्पष्ट किया कि मुद्रा लोन और स्टैंड-अप इंडिया जैसे लोन पोलिटिकल लोन हैं। सिर्फ राजनीतिक सिफारिशी को HI मिलते हैं और लौटते कभी नहीं। हम कभी भी इस तरह के लोन के पक्ष में नहीं थे। किसी को भी लोन नहीं दे सकता बैंक क्योंकि लोन देने से पहले हमे लोन वापस आने की सुरक्षा को चाक-चौबंद करना होता है।

हमारे ये पूछने पर कि छोटे और मझोले लोगों को लोन देना तो सार्वजनिक बैंकों का कार्य होना ही चाहिए, वो भी तब जब राज्य का स्वरूप कल्याणकारी है। सिंह ने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए और है भी पर लोन देना और दान देना दो अलग बातें है। लोन के नाम पर दिया जाने वाला पैसा वापस आने के उपायों के साथ दिया जाता है। आज जिस तरह सरकार संघी सिफरिशों से लोन बंटवा रही है, ये सिर्फ आंकड़ों को दर्शाने की कवायद है। जरूरत मंदों को लोन नहीं मिल रहा। अगर बैंक लोन दे रहा है तो बैंक को तय करने दो उसकी शर्तें क्योंकि लोन एनपीए होने की सूरत में सम्बंधित अधिकारी की नौकरी तक पर बात आती है।

भगोड़े माल्या को जल्द भारत ला रहे हैं और नीरव मोदी की सम्पत्ति जब्त करने जैसी अफवाहों के बीच एक खबर ये भी है कि एसबीआई अपने कर्मियों की पत्नियों को एक मोबाइल क्यूआर कोड दे रही है, जिसपर पत्नी अपने पति के देर से पहुँचने की शिकायत उच्च अधिकारी से कर सकेगी। मजे की बात ये है कि प्रशासन इससे कर्मचारी के पारिवारिक जीवन के अच्छे होने दावा कर रहा है।

अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस किस्म के लोग इस समय प्रशासन में हैं जो पहले काम करने के लिए जरूरी स्टाफ भर्ती नहीं करते और जब एक व्यक्ति पर काम का बोझ बढ़ता है तो उसके देर से घर पहुँचने की वजह भी उसी पर लाद देते हैं। अंत में ये मान कर कि सिर्फ पति ही देर से पहुँचता है एक क्यूआर कोड दे दिया गया, जबकि महिला कर्मियों की संख्या भी कुछ कम नहीं और घर पहुँचने में देर उन्हें भी होती है।

जले पर नमक भी छिड़का जा रहा है। जहाँ जरुरत बैंकों में नया स्टाफ भारती कर, नए रोजगार पैदा करने की है, वित्त मंत्री कयास लगा रहे हैं कि रोजगार है वरना इतनी शांति क्यों? साथ ही जब बैंक कर्मी विशफुल डीफाल्टरों के नाम सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं तो अगले ही दिन सरकार कहती है कि काला धन वालों के नाम नहीं बताएगी। सवाल कुछ है और जवाब कुछ, जल्द ही चुनाव आने वाले हैं और इन सभी मुद्दों को दफन कर मोदी ब्रिगेड इन्ही कालाधन वालों के पैसे से देश को बताता मिलेगा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने देश का कितना पैसा काला कर डाला है।

रोजगार नहीं तो एजुकेशन लोन कैसे चुकायें?

बैंक आफ इंडिया की 32 वर्षीय तेज तर्रार अधिकारी मीरा राय ने बताया कि अब एजुकेशनल लोन भी एनपीए होने लगे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण सरकार का नए रोजगार न पैदा करना, और निजी क्षेत्रों खास कर एफडीआइ से देश में निवेश का नहीं आ पाना शामिल है। जब रोजगार ही नहीं है तो पढाई पूरी होने के बाद युवा लोन कैसे वापस करेंगे।

साथ ही मीरा ने बैंक एसोशिएशन पर भी सवाल खड़े किये। मीरा ने बताया कि जबरन बैंक के शेयर बैंक कर्मियों को बेचे जा रहे हैं और इस मुद्दे पर प्रशासन एवं कर्मचारी संघ एक ही डाल के झूले पर पींगें बढ़ा रहे हैं। कर्मचारी संघ इस मसले पर चुप्पी साधे पड़ा है, और तो और कर्मचारियों को शेयर खरीदने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहा है जबकि सेबी के नियमानुसार ऐसा करना वर्जित है।

उधर इस मुद्दे पर एआइबीओसी सचिव सुनील लाकरा का कहना है कि किसी भी कर्मचारी को बाध्य नहीं किया गया है शेयर खरीदने के लिए। जिसकी जितनी क्षमता है ले सकता है या ना भी ले। अपने इस तर्क के पक्ष में लाकरा ने कर्मचारी संघ के व्हाट्सएप्प ग्रुप पर भेजे सन्देश को भी दिखाया जिसमे कर्मचारियों से निवेदन स्वरूप शेयर खरीदने के बात थी।

परन्तु मजदूर मोर्चा की टीम ने सचिव महोदय को वो मेसेज भी दिखाए जिसमे दिल्ली जोनल मेनेजर द्वारा दिल्ली जोन क्षेत्र के अधिकारीयों को 31 जनवरी से पहले डीमेट खाता खुलवाने और 2.5 लाख के शेयर खरीदने का निर्देश दिया गया है। इस सन्देश के बाबत किसी भी जानकारी के उपलब्ध न होने की बात कह सचिव महोदय ने अपना पीछा ऐसे कटु सवालों से छुड़ा लिया। क्या सच में एआइबीओसी अपने कर्मचारियों के हित में खड़ा है? मीरा के आरोप में दम नजर आता है।

लूट कमाई बढ़ाने के लिये, फुंकार मारनी बहुत जरूरी होती है

इसके 'अच्छे परिणाम' भी निगमायुक्त अनीता को मिलने लगे हैं

फ़रीदाबाद (म.मो.) नगर निगम में होने वाली लूट-कमाई की पुरानी खिलाड़ी रह चुकी अनीता यादव बखूबी जानती हैं कि नींबू को निचोड़ने से ही रस निकलता है। यानी जितनी सख्ती व कड़कपन के साथ फुंकार मारी जायेगी, धमकियां दी जायेंगी उतने ही ज्यादा कमाई के भाव बढ़ेंगे। इसी सिद्धांत पर चलते हुए निगमायुक्त का पद संभालते हुए अनीता ने पूरे जोर से दहाड़ कर अपने कड़े तेवरों का प्रदर्शन किया। अवैध कब्जे एवं निर्माणों को पूरी सख्ती से ध्वस्त करने का भयपूर्ण माहौल बनाया।

इसी माहौल में उनका तोड़फोड़ यानी शिकारी दस्ता बीते सोमवार को बाटा चौक स्थित पुरानी बाटा कालोनी में बने गर्म मसाला नामक रेस्तरां पर पहुंच गया। रेस्तरां फेल हो चुकने के चलते उसके मालिक ने उसी इमारत को छोटी-छोटी दुकानों आदि में परिवर्तित कर दिया था। निगमायुक्त अनीता का शिकारी दस्ता ज्वायंट कमिश्नर श्रीमती ढाका के नेतृत्व में कोई तोड़फोड़ करने नहीं गया था। वह तो केवल दहशत पैदा करके अनीता के लिए शिकार मारने गया था। जब शिकार मर गया यानी लेन-देन का सौदा पट गया तो दस्ता बिना इमारत को छूए वापस लौट आया। बहाना यह बनाया कि पुलिस बल अभी पर्याप्त नहीं है।

एन.एच-4-5 की विभाजक के.सी. रोड पर केसी सिनेमा वाले खाली प्लाट पर चल

रहे निर्माण कार्य को बीते मंगलवार को थोड़ा सा तोड़कर इशारा दिया गया कि कुछ बनाना है तो सही ढंग से सौदा पटाओ, जैसे कि इसी प्लॉट के सामने बन रहे चार प्लाटों के मालिकाना ने कर रखा है। इन प्लाटों में बेसमैंट से लेकर चौथी मंजिल तक का अवैध निर्माण कार्य बेखौफ ढंग से चल रहा हैं मजें की बात तो यह है कि केसी वाले प्लाट पर तोड़फोड़ करने आये शिकारी दस्ते ने इस सामने वाली इमारतों की तरफ झांक कर भी नहीं देखा। जाहिर है केसी वाले प्लॉट में निर्माण करने वाले को यही संदेश देना था कि लेन देन करने के बाद सब कुछ वैध हो जाता है। संदेश समझ में आ गया और उसने भी बिना कोई समय गंवाये तुरन्त सौदा पटा लिया और अगले ही दिन से निर्माण कार्य पूरी तेजी से शुरू कर दिया।

उक्त दावे तो केवल उदाहरण है वरना निगमायुक्त का शिकारी दस्ता मैडम के लिए शिकार मारने में पूरे दिलो जान से जुटा है। नगर निगम में होने वाली लूट कमाई का यह तो एक छोटा सा हिस्सा है। इससे भी बड़ी लूट ठेकों की पेमेंट व खरीददारी में होती है। पूर्व निगमायुक्त शाइन तो ऑडिट के नाम पर 20-20 साल पुरानी फाइलों में से भी मोटा माल खींचकर ले गया था तो अब अनीता कौन सी पीछे रहने वाली है।

3 करोड़ का नया जुगाड़

कंस्ट्रक्शन वेस्ट के निस्तारण हेतु 3 करोड़ की लागत से 3 प्लांट लगाने की योजना बनाई है निगमायुक्त ने। बताया जा रहा है कि अभी जो मलबा इधर उधर गलियों में बिखरा पड़ा रहता है उसको इन प्लांटों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के तौर पर तैयार किया जा सकेगा। इससे मलबा फैंकने वाले को भी कुछ लाभ मिल सकेगा और भवन निर्माण करने वाले को भी कुछ सस्ती सामग्री मिल सकेगी। इसी नगर निगम का यदि ट्रैक रिकार्ड देखें तो पता चलता है कि न तो इनके सोलिड वेस्ट प्लांट कभी चले और न ही एसटीपी सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट जबकि इन पर सैकड़ों रुपया बर्बाद किया जा चुका है। ऐसे ही इनके मलबा प्लांट चलेंगे। हां निगम वालों की लूट कमाई जरूर अच्छी हो जायेगी।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06